

## अनाधिकृत नरिमाणों को ध्वस्त करने हेतु नए नयिम

### चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाधिकृत नरिमाणों को ध्वस्त करने से पहले एजेंसियों के लिये दशा-नरिदेश जारी किये हैं।

- ध्वस्तीकरण को अंतमि रूप देने से पहले नोटसि अवश्य दया जाना चाहयि तथा व्यक्तगित सुनवाई का अवसर भी प्रदान कया जाना चाहयि।

### मुख्य बढि

- ध्वस्तीकरण के नये नयिम:

- अनविर्य कारण बताओ सूचना एवं प्रतीक्षा अवधः

- कारण बताओ सूचना जारी कयि बना कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य नहीं कया जाना चाहयि।
- एजेंसियों को ध्वस्तीकरण का आदेश देने से पहले नोटसि प्राप्ती की तारीख से **15 दनि तक प्रतीक्षा करनी होगी**। नयिम अपील का अवसर प्रदान करते हैं, अंतमि आदेश के बाद **15 दनों** के लिये ध्वस्तीकरण में देरी होनी चाहयि।
- मालकों/कब्जेदारों को अनाधिकृत संरचनाओं को स्वयं हटाने या ध्वस्त करने के लिये **15 दनि का समय** दया जाना चाहयि।

- पारदर्शता उपाय:

- नोटसि, उत्तर और आदेश सहति सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण करने के लिये तीन महीने के भीतर एक [डजिटल पोर्टल](#) स्थापति कया जाना चाहयि।
- **नोटसि ज़िला मजसिस्ट्रेट (DM) कार्यालय को ईमेल के माध्यम से** स्वचालति पावती के साथ भेजे जाने चाहयि।
- व्यक्तगित सुनवाई के वविरण अवश्य दर्ज कयि जाने चाहयि।

- वधिवंस आदेश एवं अनुपालन:

- अंतमि आदेश में नमिनलखिति का उल्लेख होना चाहयि:
  - क्या संरचना **समझौता योग्य है** (शुल्क देकर नयिमति कया जा सकता है)।
  - **अनाधिकृत/गैर-शमनीय** भागों का वविरण।
  - वधिवंस क्यों आवश्यक है?
- इन नयिमों का पालन न करने पर अधिकारियों के वरिद्ध **अवमानना कार्यवाही** और **अभयोजन चलाया जा सकता है**।

- कानूनी एवं प्रशासनकि टपिणयिः

- नये नयिमों में कई कदम पहले से ही वभिन्न अधनयिमों के अंतरगत मौजूद हैं।
- नई सुवधियों का उद्देश्य ध्वस्तीकरण में **पारदर्शता और स्थरिता में सुधार लाना है**।
- ज़ल्दबाजी में कयि गए **ध्वस्तीकरण और पुराने ध्वस्तीकरण आदेशों के लंबति रहने के कारण कदाचार और अनाधिकृत नरिमाण को बढावा मलिता है**।
- नगर नगिम के अधिकारियों ने अनुपालन की पुष्टि की और स्पष्ट कया कि अस्थायी अतकिरणों से **उत्तर प्रदेश नगर नगिम अधनयिम, 1959** के तहत नपिटा जाएगा।